फर्जी बीपीएड डिग्री से बना शारीरिक शिक्षक एसओजी के शिकंजे में फंसा

एस.ओ.जी. ने आरोपी शिक्षक राजेश कुमार को अलवर से दबोचा

■ जांच में सामने आया कि आवेदन के समय आरोपी राजेश कुमार फागणा के पास यह योग्यता मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने कथित रूप से फर्जी तरीके से आवेदन में बी.पी.ई.एड योग्यता दर्शाई।

जयपुर (कासं)। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) राजस्थान ने शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में फर्जी बी.पी.एड डिग्री के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी शारीरिक शिक्षक राजेश कुमार फागणा को अलवर से गिरफ्तार किया है। आरोपी कोटपूतली-बहरोड़ जिले के फागणों की ढाणी, खड़ब का निवासी है।

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विशाल बंसल ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा-2022 में बी.पी.ई.एड की मार्कशीट अनिवार्य शैक्षिणक योग्यता थी। जांच में सामने आया कि आवेदन के समय आरोपी राजेश कुमार फागणा के पास यह योग्यता मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने कथित रूप से फर्जी

आरोपी शिक्षक राजेश कुमार

तरीके से आवेदन में बी.पी.ई.एड योग्यता दर्शाई।

जांच के अनुसार आरोपी ने बाद में जे.एस.विश्वविद्यालय से शिक्षा सत्र 2017-19 की बैक-डेट में तैयार करवाई गई फर्जी बी.पी.ई.एड डिग्री और मार्कशीट हासिल की। यह डिग्री कथित रूप से दलाल पंकज जैन और पवन सिंह चौहान के माध्यम से तैयार करवाई गई थी। इसी आधार पर आरोपी ने वर्ष 2023 में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मारकपुर, गोविंदगढ़ (अलवर) में शारीरिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त कर ली। एसओजी ने इस मामले में आरोपी राजेश कुमार फागणा, जे.एस. यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों तथा अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने पंकज जैन और पी.एस. चौहान के साथ मिलकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों सुकेश कुमार और नंदन कुमार मिश्रा की मिलीभगत से फर्जी डिग्री तैयार करवाई थी। इस मामले में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर सुकेश कुमार और नंदन कुमार मिश्रा को 6 मार्च को गिरफ्तार कर 9 मार्च को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वहीं मुख्य आरोपी राजेश कुमार फागणा, पंकज जैन और पी.एस. चौहान गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे।

एसओजी ने जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर 17 मई को राजेश कुमार फागणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

नशे की खेप के साथ अफ्रीकन महिला गिरफ्तार

जयपुर। डीआरआई (राजस्व आसूचना निदेशालय) ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 19 मई को मुंबई जाने वाली बस से यात्रा कर रही विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। खूफिया सूचना के आधार पर डीआरआई ने विदेशी महिला को जयपुर में रोका। इस विदेशी महिला के ट्रॉली बैग की गहन जांच एवं तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 2256 ग्राम मेथामफेटामाइन, 142 ग्राम कोकीन/मेथाक्वालोन तथा 46 ग्राम /एक्स्टेसी टैबलेट बरामद किए। बरामद मादक पदार्थों का कुल अनुमानित अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 2.56 करोड़ आंका गया है।

इन मादक पदार्थों को ट्रॉली बैग में रखे कपड़ों और तकिये के कवर आदि में बड़ी चतुराई से छिपाकर रखा गया था, ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला मादक पदार्थों की तस्करी कर उन्हें अन्य राज्यों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। डीआरआई जयपुर की टीम ने आरोपी महिला को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

नीति आयोग ने की राजस्थान के ''शिक्षा मॉडल'' की सराहना

■ नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट' में राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों की तारीफ की है।

■ रिपोर्ट में राज्य सरकार के 'शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान' और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को 'गुड स्टेट प्रैक्टिसेज' के रूप में शामिल किया गया है।

जयपुर (कासं)। नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट' में राजस्थान के शिक्षा क्षेत्र में किए गए नवाचारों की सराहना की है। रिपोर्ट में राज्य सरकार के 'शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान' और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को 'गुड स्टेट प्रैक्टिसेज' के रूप में शामिल किया गया है।

रिपोर्ट में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, फिटनेस और स्वास्थ्य निगरानी के लिए विकसित तकनीक आधारित मॉडल को प्रभावी बताया गया है। इसके तहत प्रदेश में 75 लाख से अधिक विद्यार्थियों की 70 से ज्यादा स्वास्थ्य मानकों पर स्क्रीनिंग की गई। विद्यार्थियों की दृष्टि, श्रवण क्षमता, पोषण स्तर, दंत स्वास्थ्य और शारीरिक फिटनेस की जांच के साथ मोबाइल ऐप आधारित फॉलो-अप प्रणाली भी विकसित की गई है। नीति आयोग ने इसे नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था में स्वास्थ्य और पोषण को समाहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया है। रिपोर्ट में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ओसीआर तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मूल्यांकन प्रणाली की भी विशेष सराहना की गई है।

आयोग के अनुसार इस प्रणाली के माध्यम से 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लर्निंग पॉवर्टी से बाहर निकालने में मदद मिली है। साथ ही विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में प्रतिवर्ष 8 से 10 प्रतिशत तक सुधार दर्ज किया गया। राजस्थान परख रिपोर्ट-2024 में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल रहा। रिपोर्ट में टोंक जिले में संचालित 'पढ़ाई विद एआई' कार्यक्रम का भी उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से गणित सहित विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों की उत्कृष्ट पाठशाला के रूप में उभर रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक के समन्वित उपयोग पर आधारित इन पहलों को नीति आयोग ने अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बताया है।

छह राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ हार्डकोर बदमाश गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से 27.50 लाख रु. नकद और गहने बरामद

जयपुर (कासं)। विधायकपुरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छह राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने पांच हजार रुपए के इनामी हार्डकोर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चोरी, लूट, डकैती और हत्या जैसी गंभीर वारदातों में वांछित था।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षिराज ने बताया कि आरोपित विजय लाम्बा 28 जनवरी 2026 को भागीरथ कॉलोनी स्थित एक मकान में हुई लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी की वारदात का मुख्य सरगना है। इस घटना के संबंध में परिवादिया रचना सबीखी ने विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज कराया था कि 28 जनवरी की शाम परिवार घर से बाहर गया हुआ था। वापस लौटने पर मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी मिली, सीसीटीवी कैमरे क्षितग्रस्त थे और अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने व नकदी गायब मिले। इस मामले में विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। इधरघटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस

आरोपी विजय लाम्बा

उपायुक्त ललित किशोर शर्मा और सहायक पुलिस आयुक्त अशोक नगर बालाराम के सुपरविजन में थानाधिकारी नरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। जांच के दौरान पुलिस ने पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर 25 लाख रुपए नकद और लाखों के गहने बरामद किए थे। इसके बाद में तकनीकी इनपुट और पूछताछ के आधार पर मुख्य आरोपी विजय लाम्बा की तलाश की गई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है और वहां वांछित चल रहा है। इसके बाद जयपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर केंद्रीय जेल बिलासपुर से आरोपी विजय लाम्बा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी की राशि में से 2.50 लाख रुपए नकद और बरामद किए गए। इस तरह पूरे मामले में अब तक कुल 27.50 लाख रुपए नकद और लाखों के गहने बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार 52 वर्षीय विजय लाम्बा मूल रूप से विकासपुरी, नई दिल्ली का निवासी है और वर्ष 1995 से अधिकतर समय जेल में रहा है। हत्या के एक मामले में वर्ष 2023 में जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से अपनी गैंग सक्रिय कर दी थी। आरोपी पॉश इलाकों और ज्वेलरी शोरूम की रेकी कर रात के समय सुनियोजित तरीके से वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। पूछताछ में अन्य राज्यों में हुई चोरी और लूट की कई बड़ी वारदातों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।

स्वगणना में जयपुर जिले ने प्राप्त किया प्रथम स्थान

जयपुर। जनगणना संचालन 2026 के अंतर्गत संचालित स्वगणना अभियान में जयपुर जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले द्वारा अब तक 3.25 लाख से अधिक स्वगणना दर्ज की गई हैं, जो राज्य की कुल स्वगणना उपलब्धि का लगभग 22 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि जनगणना के प्रति व्यापक जनजागरूकता, प्रभावी प्रचार-प्रसार तथा जनगणना कार्मिकों एवं अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी और समर्पित प्रयासों का परिणाम है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से निरंतर जनसंपर्क एवं जागरूकता गतिविधियां संचालित की गईं, जिससे आमजन ने उत्साहपूर्वक स्वगणना अभियान में सहभागिता निभाई। इस उत्कृष्ट उपलब्धि पर राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास द्वारा जिला कलेक्टर संदेश नायक एवं नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा को सम्मानित किया गया। दोनों अधिकारी जयपुर जिले के प्रधान जनगणना अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं तथा उनके नेतृत्व में यह अभियान सफलतापूर्वक संचालित किया गया। जिला प्रशासन ने जनगणना 2026 के सफल संचालन और आमजन की सहभागिता के लिए गतिविधियां निरंतर जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया है।

विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पीहर पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया

■ फंदे पर लटका मिला शव, मामले की जांच को लेकर थाने पर विरोध प्रदर्शन

जयपुर। आमेर इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जहां नाईयों के मोहल्ले में रहने वाली 32 वर्षीय रेखा सेन का शव बुधवार सुबह घर में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम की मौजूदगी में शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए आमेर स्थित राजकीय अस्पताल भिजवाया।

थानाधिकारी गौतम डोटासरा ने बताया कि रेखा सेन की शादी करीब 11 वर्ष पहले विष्णु सेन से हुई थी। महिला अपने पति और 8 वर्षीय बेटे के साथ रहती थी। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लिया गया है।

इधर घटना की सूचना मिलते ही पीहर पक्ष के 50 से अधिक लोग आमेर थाने पहुंच गए और पति व ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर कई घंटों तक धरने पर बैठे रहे। मृतका की मां सरोज देवी ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मंगलवार शाम रेखा से फोन पर बात हुई थी। तब उसने घर में परेशानी होने की बात कही थी। मृतका की बहन चंचल सेन ने आरोप लगाया कि पति विष्णु सेन कोई काम नहीं करता था और रेखा ही निजी नौकरी कर परिवार का खर्च चलाती थी। परिवार में अक्सर विवाद होता रहता था। परिजनों का आरोप है कि मंगलवार रात रेखा के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतका के रिश्तेदार अभिषेक सेन ने बताया कि दो माह पहले भी रेखा के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया था। परिवार ने सास, पति और देवर पर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सार-समाचार

आमेरा ने सहकारिता के नवाचारों को सराहा

जयपुर। ऑल राजस्थान को-आपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन, ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव एवं सहकारी साख समितियों एम्पलाईज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने बताया कि विभाग में अनुशासन कायम करने के लिए सहकारिता मंत्री के निर्देशानुसार सभी पुरुष एवं महिला कार्मिकों की समान रूप से बायोमैट्रिक उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य रूप से लागू कर डॉ. समित शर्मा ने सराहनीय प्रशासनिक मिसाल पेश की है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय का हम पैक्स से अपैक्स तक संगठन की ओर से स्वागत करते है। साथ ही सभी पुरुष एवं महिला कार्मिकों की अपनी सीट पर कार्य की टू-डू-लिस्ट बनवाकर कार्य के प्रति जवाबदेही एवं जिम्मेदारी लागू की गई, जिससे समय पर त्वरित निष्पादन हो रहा है। अधिकांश कार्मिकों ने इस क्रांतिकारी पहल को सहर्ष स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि मंत्री गौतम दक एवं डा. समित शर्मा के कुशल नेतृत्व एवं प्रशासन से सहकारिता में जवाबदेह, भ्रष्टाचार-मुक्त कुशल कार्य संस्कृति की पुनर्स्थापना हुई है जो स्वागत योग्य है। सहकारिता में सुधार से सुविधाभोगी कार्य संस्कृति के पुराने ढर्रे में बदलाव से कुछ विघ्न संतोषी तत्वों द्वारा व्यवस्था का विरोध कर इसे अनावश्यक लिंग भेद रंग देने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है। इस तरह के सभी कृत्यों का, सहकारिता विभाग के विरुद्ध तथ्यहीन मनगढ़ंत समाचार पत्रों एवं सोशल मिडिया पर प्रचारित करवाने का हम पैक्स से अपैक्स तक संगठन की ओर से विरोध करते है, ऐसे तथ्यहीन प्रकाशित समाचारों की भर्त्सना करते है।

कैलाश शर्मा बने राजस्थान प्रदेश प्रमुख

जयपुर। मानवाधिकार विकास संघ की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने जयपुर निवासी कैलाश शर्मा (राष्ट्रदूत) को राजस्थान प्रदेश प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। उन्हें राजस्थान की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। संगठन की ओर से उन्हें बधाई देते हुए कहा गया कि कैलाश शर्मा की नेतृत्व क्षमता, कार्यशैली और समर्पण पर हमें पूर्ण विश्वास है। हमें पूर्ण भरोसा है कि वे मानवाधिकार विकास संघ के उद्देश्यों को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पुलिस गश्ती दल से मारपीट, चार गिरफ्तार

जयपुर। ब्रह्मपुरी इलाके में रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है। गोविंद नगर वेस्ट में देर रात गली के बाहर बैठे युवकों को टोकना पुलिस दल को भारी पड़ गया। नाराज युवकों और उनके परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई कर थप्पड़-मुक्कों से हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी हेमंत जनागल ने बताया कि घटना 16 और 17 मई की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे की है। हेड कांस्टेबल सुशीन लाल, राम मनोहर और होमगार्ड जवान गगन सिंह पुलिस जीप से क्षेत्र में रात्रिकालीन गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गोविंद नगर वेस्ट की एक गली में तीन युवक बाहर बैठे दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों द्वारा पूछताछ करने पर एक युवक वहां से चला गया, जबकि दो युवक पुलिस दल से बहस करने लगे। समझाइश कर घर जाने के लिए कहने पर दोनों युवक अड़ गए और शोर मचाकर अपने परिवार के लोगों को भी बाहर बुला लिया। इसके बाद परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। आरोप है कि पुलिस दल पर थप्पड़-मुक्कों से हमला किया गया। मारपीट के दौरान होमगार्ड जवान गगन सिंह की सोने की चेन भी टूटकर गिर गई। घटना की सूचना मिलने पर ब्रह्मपुरी थाना पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता मौके पर पहुंचा और आरोपी जगजीत, उसकी पत्नी निशा, बेटे तथा चचेरे भाई रिची तलवार को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा उत्पन्न करने और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने का मामला दर्ज किया है।

खूंखार और रेबीज संक्रमित कुत्तों के लिए जयपुर में बनेंगे दो नए शेल्टर होम

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जयपुर नगर निगम ने डॉग बाइट की घटनाओं की रोकथाम के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। निगम शहर में खूंखार और रेबीज संक्रमित आवारा कुत्तों को रखने के लिए दो नए शेल्टर होम बनाएगा। ये शेल्टर होम हिंगोनिया और लांगडियावास क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए निगम ने टैंडर सहित अन्य प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार निगम की टीमें शहरभर में अभियान चलाकर रेबीज और खूंखार कुत्तों की पहचान करेंगी तथा उन्हें पकड़कर अलग-अलग शेल्टर होम में रखा जाएगा। रेबीज संक्रमित कुत्तों के संबंध में इलाज या यूथेनेशिया (दया मृत्यु) का निर्णय चार डॉक्टरों की समिति करेगी। निगम के अनुसार रेबीज संक्रमित कुत्तों की पहचान उनके व्यवहार और लक्षणों के आधार पर की जाएगी। ऐसे कुत्तों को पानी से डर लगता है और उनके मुंह से लगातार लार टपकती रहती है। निगम द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक शेल्टर होम में एक हजार कुत्तों को रखने की व्यवस्था होगी। इसके लिए एक हजार केनल्स बनाए जाएंगे। यहां कुत्तों के उपचार, भोजन और देखभाल की समुचित सुविधाएं विकसित की जाएंगी। बाजार और सार्वजनिक स्थानों से पकड़कर लाए गए कुत्तों को चार से पांच दिन तक शेल्टर होम में रखा जाएगा, जिसके बाद समिति की अनुशंसा पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में नगर निगम के पास केवल लगभग 500 कुत्तों को रखने की क्षमता है। निगम फिलहाल एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण के बाद पुनः उनके क्षेत्र में छोड़ा जाता है। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार शहर में वर्तमान में लगभग 1.35 लाख कुत्ते हैं, जबकि पालतू कुत्तों की संख्या 10 हजार से अधिक आंकी गई है।

'अनुकंपा नियुक्ति से नहीं किया जा सकता वंचित'

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के दौरान स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसके आश्रित को इस आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना नए नियम लागू होने के पहले हुई थी। इसके साथ ही अदालत ने पशुपालन विभाग को कहा है कि वह याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने पर पुनः विचार करे। अदालत ने विभाग के नियुक्ति नहीं देने के आदेश को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया है कि विभाग नियुक्ति पर विचार करते समय दुर्घटना होने की समय को ध्यान में नहीं रखेगा। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश करण प्रताप सिंह राठौड़ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता महेन्द्र प्रताप सिंह पशुपालन विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी थे। एक हादसे में 1 जुलाई, 2021 को वे गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में स्थायी दिव्यांग होकर कोमा की स्थिति में चले गए। मेडिकल बोर्ड ने भी उनमें सुधार की संभावना से इनकार करते हुए 85 फीसदी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। याचिकाकर्ता की ओर से स्थायी दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति देने के संबंध में साल 2023 में बने नियमों के तहत आवेदन किया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए नियुक्ति से इनकार कर दिया कि उसके पिता की दुर्घटना नियम लागू होने से पहले हुई थी। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि इस संबंध में बने नियमों का उद्देश्य पीड़ित परिवार को राहत देना होता है। ऐसे में यह अप्रासंगिक है कि दुर्घटना पहले हुई या बाद में। इसके अलावा नियम लागू होने के बाद भी याचिकाकर्ता के पिता दिव्यांग स्थिति में ही हैं और सेवा में बने हुए हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए।

नीट पेपर लीक के विरोध में आज घेराव करेगी कांग्रेस

जयपुर। नीट-2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले और इसमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता के आरोपों को लेकर राजस्थान कांग्रेस गुरूवार को जयपुर में भाजपा प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन का नेतृत्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं मीडिया चेयरपर्सन स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि लगातार नीट परीक्षा के पेपर लीक मामलों को रोकने में केंद्र सरकार विफल रही है और जिम्मेदार लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे तथा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग करने की मांग कर रही है। प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ता गुरूवार सुबह 10 बजे जयपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर एकत्रित होंगे। इसके बाद कार्यकर्ता जुलूस के रूप में शहीद स्मारक होते हुए भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे।

'हर जिले में मॉडल फैसिलिटी के रूप में विकसित होंगे अस्पताल'

जयपुर। प्रदेश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत सभी जिलों में एक-एक राजकीय एवं निजी स्वास्थ्य संस्थान का चयन किया गया है और अब इन्हें मॉडल फैसिलिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन संस्थानों पर आयुष्मान डिजिटल मिशन कम्प्लायंट व हैल्थ मैंनेंजमेंट इन्फोर्मेशन सिस्टम में इम्प्लेमेंट करके, हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री तथा हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री में पंजीकृत करवाया जाएगा। इसके लिए राजकीय व निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराके एबीडीएम आईडी तैयार करनी होगी। निजी अस्पतालों को इसकी विस्तृत जानकारियां देने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार को सीफू में एबीडीएम मॉडल फैसिलिटी पर राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई।

मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. जोगाराम ने कार्यशाला में बताया कि एबीडीएम मॉडल आभा आईडी वाले सभी मरीजों का स्वास्थ्य व उपचार से संबंधित रिकार्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा, जिससे अस्पतालों को भी उपचार करने में सुविधा रहेगी। उन्होंने बताया कि सम्पूर्ण भारत के सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के अस्पतालों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण करना होगा और निर्धारित आईडी प्राप्त कर आवश्यक सूचनाएं अपलोड करनी होंगी। उन्होंने बताया कि एबीडीएम इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉडल फैसिलिटी के रूप में चयनित संस्थानों को पूरी तरह से स्पेशल सपोर्ट देकर डिजिटल किया जाएगा और इनमें एंड-टू-एंड आईबीडीएम के सभी कॉम्पोनेन्ट जैसे- स्कैन एंड शेयर, एबीडीएम कम्प्लायंट हेल्थ मैजेंटमेंट इंफोर्मेशन सिस्टम एडॉप्शन, हेल्थकेयर फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री करवाकर, सभी पेशेंट का आभा आई डी बनाकर हेल्थ रिकॉर्ड लिंक किया जाएगा।

अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी.शुभमंगला ने कहा कि ये मॉडल संस्थान एबीडीएम इम्प्लीमेंटेशन के लिए मॉडल फैसिलिटी के रूप में चुने गए हैं और इन्हें स्पेशल सपोर्ट देकर डिजिटल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य सेवाएं एकीकृत हो रही हैं और सभी श्रेणी के चिकित्सा संस्थानों व मरीजों का यूनिक आईडेंटीफिकेशन होने से स्वास्थ्य प्रबंधन आसान हो जायेगा। कार्यशाला में सीईओ राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी हरजी लाल अटल, ओएसडी एनएचएम संतोष गोयल ने भी आवश्यक जानकारियां दी।

नेशनल हैल्थ अॅथारिटी के निदेशक पकंज अरोड़ा ने वीसी के माध्यम से, स्टेट नोडल अधिकारी आईटी विष्णुकांत और स्टेट एबीडीएम टीम की प्रोग्राम मैनेजर पिंकी बूलचंदानी ने प्रजेंटेशन के माध्यम से मॉडल अस्पतालों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारियां दी।

जयपुर में शीघ्र शुरू होगी सहकारी मॉडल पर आधारित 'भारत टैक्सी' सेवा

'दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और चंडीगढ़ के बाद अब यहां भी मिलेगा परिवहन का किफायती और सुरक्षित विकल्प'

जयपुर (कासं)। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम कुमार दक ने कहा कि सहकारी मॉडल पर आधारित भारत की पहली टैक्सी सेवा 'भारत टैक्सी' का शीघ्र ही जयपुर में भी शुभारंभ होगा। यह सेवा आमजन को किफायती और सुरक्षित परिवहन का विकल्प उपलब्ध कराएगी। साथ ही, 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करते हुए सारथियों (चालकों) की आर्थिक उन्नित का आधार भी बनेगी।

सहकारिता मंत्री बुधवार को अपेक्स बैंक सभागार में भारत टैक्सी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सारथियों (चालकों) को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली, लखनऊ, मुम्बई और चण्डीगढ़ के बाद अब जयपुर सहित अन्य शहरों में शीघ्र भारत टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। जयपुर में जून माह के

सहकारिता मंत्री गौत्तम कुमार दक ने बुधवार को अपेक्स बैंक सभागार में भारत टैक्सी संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत सारथियों (चालकों) से सुझाव जाने।

प्रथम सप्ताह में इस सेवा की शुरूआत प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी एक ऐसी अनूठी सेवा है, जिसमें मालिक कोई बाहरी व्यक्ति या कम्पनी नहीं होकर स्वयं टैक्सी चलाने वाले सारथी हैं। यह सेवा स्वामित्व, सुरक्षा कवच, सम्मान और लाभांश का समान वितरण के चार मूल विचारों पर आधारित है। इसमें टैक्सी चलाने वाला सारथी ही कंपनी का वास्तविक मालिक होगा।

दक ने कहा कि भारत टैक्सी में किसी भी सारथी का अकाउंट बिना सुनवाई के बंद नहीं किया जाएगा। भारत टैक्सी से सारथियों को हिडन चार्जेज से भी मुक्ति मिलेगी। सारथियों को विकल्प उपलब्ध होने से निजी कम्पनियों की मनमानी पर अंकुश लगेगा। इस प्रकार, सहकार टैक्सी सारथियों के जीवन, आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति में परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। सहकारिता मंत्री ने सारथियों से आ ान किया कि वे अन्य चालकों को भी इसके फायदों की जानकारी देकर अधिक से अधिक संख्या में उन्हें भारत टैक्सी के साथ जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएं।

इस अवसर पर सारथियों ने अपने अनुभव एवं सुझाव साझा करते हुए कहा कि वे भारत टैक्सी की शुरूआत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निजी कम्पनियों के साथ कार्य करने में उन्हें विभिन्न प्रकार से शोषण का सामना करना पड़ता है और उनकी आमदनी में भी अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। सारथियों ने कहा कि यह हर्ष का विषय है कि भारत टैक्सी स्वदेशी सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित होगी, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी की शुरूआत से उन्हें निजी कम्पनियों के मनमाने सब्सक्रिप्शन चार्जेज से भी मुक्ति मिलेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे भारत टैक्सी के संचालन में राजस्थान को रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने में पूरे मनोयोग से अपनी भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर विशिष्ट सहायक डॉ. सूरज सिंह नेगी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मा.सं.वि.) भोमाराम, अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीत सिंह चूंडावत एवं भारत टैक्सी के सिटी हैड (जयपुर) अभिषेक चारण उपस्थित रहे।